

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक



बाघों के दुश्मन

कभी गूंजती थी दहाड़, वहां है सन्नाटा
आखिर कहां गया भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ?

युगांतर प्रकृति

प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित मासिक पत्रिका

प्रकृति, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान, क्षमता संवर्धन शोध

एवं विकास तथा राष्ट्रीय गौरव के लिए समर्पित संस्था

सदस्यता शुल्क

1	वार्षिक	250/-
2	पंचवर्षीय	1,200/-
3	दस वर्षीय	2400/-
4	आजीवन	5,000/-

विज्ञापन दर

1	बैक पेज	1,00,000/-
2	इनसाइड कवर पेज	90,000/-
3	फुल पेज	75,000/-
4	हाफ पेज	50,000/-

भुगतान संबंधित निर्देश

भुगतान कृपया चेक/डीडी/आरटीजीएस द्वारा Nature Foundation के नाम से करें

Account Details

NATURE FOUNDATION

Account No. : 3611740792

Kotak Mahindra Bank

IFSC Code : KKBK0005631

विज्ञापन संबंधित निर्देश

कृपया अपना विज्ञापन पीडीएफ

अथवा जेपीजी फॉर्मेट में

yugantarprakriti@gmail.com

ईमेल या डाक द्वारा युगांतर प्रकृति, सेंद्रल

स्कूल के समीप, सिद्रोल, नामकुम,

रांची-834010 के पते पर भेजें।

विशेष सहयोग

‘युगांतर प्रकृति’ का प्रकाशन नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। पत्रिका के सुगम प्रकाशन हेतु Nature Foundation के नाम चेक अथवा डीडी के माध्यम से यथासंभव आर्थिक सहयोग आमंत्रित है।

इस अंक में खास...



06 बाघों के दुश्मन

कभी गूंजती थी दहाड़, वहां है सन्नाटा
आखिर कहा गया भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ?



12

विशेष

नदियों में बह रहा
धीमा जहर

अमेरिका के तुलाने विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं।

विशेष दिवस

14

झारखंड सरकार के प्रयास और वृक्ष कटाव रोकने की पहल झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगलों का देश, अपने घने जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।



मेहमान का पन्ना

18



कठोर फैसले करें, तभी मिलेगी प्लास्टिक से मुक्ति



22

सारंडा पर सेमिनार

सारंडा का बदलाव अब दिखने लगा है: सरयू राय
जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और सारंडा बचाओ अभियान के संयोजक सरयू राय ने कहा है कि अब सारंडा बदल रहा है।



24

आयोजन

प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने से पर्यावरण की समस्या बड़ी : सरयू राय



28

स्वच्छता

नदियों की स्वच्छता के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी : राज्यपाल

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक
वर्ष-9, अंक-04, जुलाई-2025, कुल पृष्ठ-36 (आवरण सहित)

मुख्य संरक्षक
सरयू राय

प्रधान संपादक
आनंद सिंह

संपादक
अंशुल शरण

संरक्षक मंडल
राजेन्द्र सिंह, एम.सी. मेहता, प्रो. आर. के. सिन्हा,
प्रो. एस. इ. हसनैन, डॉ. आर. एन. शरण,
डॉ. आर. के. सिंह

सलाहकार मंडल
डॉ. एम. के. जमुआर, डॉ. दिनेश कुमार मिश्र,
डॉ. के. के. शर्मा, डॉ. गोपाल शर्मा,
डॉ. ज्योति प्रकाश

डिजाइन आर्टिस्ट
अनवारूल हक

विधि परामर्शी
रवि शंकर (अधिवक्ता)

प्रबंधन
राजेश कुमार सिन्हा

संपादकीय कार्यालय

संपादकीय, सदस्यता एवं विज्ञापन
नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप
पो. नामकूम, सिदरौल, रांची, झारखंड, पिन-834010

कोलकाता कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, 131/24, रीजेंट पार्क गवर्नमेंट क्वार्टर,
कोलकाता, पिन-700040

पटना कार्यालय

201, दीपराज कॉम्प्लेक्स, आर्य कुमार रोड,
दिनकर गोलंबर, पटना 834004

स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक मधु द्वारा झारखंड प्रिंटर्स
प्रा. लि., 6A, गुरुनानक नगर, साकची, जमशेदपुर से
मुद्रित व नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप
पो. नामकूम, सिदरौल, रांची, झारखंड से प्रकाशित।
आरएनआई नंबर: JHAHIN/2016/68667
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर: RN/248/2016-18

ई-मेल: yugantarprakriti@gmail.com
मोबाइल 7307071539, 9304955301/2

■ अपनी बात



■ अंशुल शरण

सोच हो तो जिम्मेदारी भरी

प्रिय पाठकों,

यह जुलाई का महीना है और इस माह में पर्यावरण को लेकर विश्व भर में कई आयोजन होने हैं। बीते जून माह में आपने देखा होगा कि देश-दुनिया में किस तरीके से पर्यावरण दिवस मनाया गया। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्योंकि उन्हें इस धरा की चिंता थी। उन्हें इस बात की चिंता रही है कि आने वाले दिनों में पृथ्वी का जीवन कैसा रहेगा। नई पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए वो क्या चीजें हैं, जो अभी से करने की जरूरत है। यह जिम्मेदारी भरी सोच ही आपको शेष लोगों से अलग करती है।

आपकी मासिक पत्रिका युगांतर प्रकृति ने भी विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 4 जून को एक बड़ा कार्यक्रम जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय में आयोजित किया था, जो मूलतः पर्यावरण जागरूकता के संबंध में कक्षा 6 से 11 तक के बच्चों के लिए था। जमशेदपुर के दो दर्जन से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था और पर्यावरण के प्रति अपनी सोच को सवाल-जवाब, चित्रकला, भाषण और निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह एक बेहतरीन आयोजन था, जिसकी सराहना बच्चों के अभिभावकों ने की। बच्चे तो बच्चे, उनके माता-पिता भी पर्यावरण के प्रति यहां से जागरूक होकर गये। दरअसल, किसी भी आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य जन-जागरूकता ही होती है। जैसे, जुलाई माह में विश्व बाघ दिवस है। अब बाघ तो सभी के कौतूहल का केंद्र बन ही जाते हैं। चिड़ियाघर में आप बाघ को देखने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। एक बार जैसे ही आपको बाघ दिख जाता है, आप खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। अब तो लोग एआई के माध्यम से बाघ के साथ अपनी तस्वीरें भी बनाने लगे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे हैं। तो, बाघ एक कौतूहल के साथ-साथ आकर्षण का भी केंद्र है। लेकिन, इनकी दुनिया भर में संख्या कितनी रह गई है, इस पर बहुत कम लोग सोचते हैं। बाघ, बाघ है। वह हमारे मनोरंजन का केंद्र बिंदु क्षण भर के लिए हो सकता है, आजीवन के लिए नहीं। प्रकृति प्रदत्त इस पारिस्थितिकी को ठीक रखने के लिए भारत जैसे देश में बहुत सारे बाघ चाहिए। इनकी संख्या अभी 3600 के करीब है जो कम ही मानी जाएगी। इनकी संख्या दोगुनी करने की जरूरत है।

जुलाई में सिर्फ बाघ दिवस ही नहीं है। विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी है। इसी माह में चिम्पांजी और सांप दिवस भी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो प्रकृति और पर्यावरण को लेकर दुनिया के कई देशों में साल भर कोई न कोई आयोजन होते रहते हैं। हम लोग कुछ खास दिवसों की ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इनसे हमारा साबका पड़ता है।

अभी भारत में पर्यावरण की क्या स्थिति है, यह आपसे छुपी नहीं है। ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड और गर्मी और ठंड, दोनों में बारिश का होना आपने महसूस किया होगा। यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, यह आपको पता ही होगा। आखिर हम लोग पर्यावरण के मिजाज को कब समझेंगे?

प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करने की बात लगातार की जाती रही है लेकिन न दुकानदार प्लास्टिक बैग में सामान देना बंद करता है, न हम उसे सामान लेने के लिए जूट का बैग देते हैं। चुनांचे, प्लास्टिक के बैग अभी चलन में हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए घोर परेशानी का सबब है। जुलाई माह में आप, आपके घरवाले यह वादा करें कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक हो या फिर किसी अन्य क्वालिटी का प्लास्टिक, वे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ पैसे लगाकर जूट के या कपड़े का थैला खरीदेंगे और जो सामान लाना है, उसी में लाएंगे। अगर आप आज प्लास्टिक बैग को ना कहते हैं तो मान कर चलें कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक बैग का नामोनिशान मिट जाएगा।

इस अंक को संग्रहणीय बनाने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण से संबंधित कुछ बड़े आयोजनों की रिपोर्ट भी है। पढ़ कर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक पढ़ते रहें युगांतर प्रकृति.....!

आपका ही

(अंशुल शरण)

मनुष्य के लिए चिम्पांजी और चिम्पांजी के लिए इंसान खतरनाक

चिम्पांजी मूलतः वानर हैं। इन्हें महान वानर मान लिया गया है। इंसान और चिम्पांजी में सबसे बड़ी समानता यह है कि इनका और इंसान का डीएनए करीब 96 प्रतिशत तक मिलता है। दुनिया भर में इस प्राणी को संरक्षित करने का अभियान चलता है। 14 जुलाई को हर साल विश्व चिम्पांजी दिवस मनाया जाता है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

चिम्पांजी भूमध्यरेखीय अफ्रीका के जंगलों और सवाना में पाए जाते हैं। वर्तमान में उनका क्षेत्र 21 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। चिम्पांजी आवास के नुकसान और शिकार के कारण खतरे में हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में जंगल में 170,000 से 300,000 चिम्पांजी रह रहे हैं। प्रोजेक्ट चिम्पकेयर जनगणना के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2,000 चिम्पांजी हैं। एक समय में, इनमें से अधिकांश चिम्पांजी प्रयोगशालाओं में रहते थे, लेकिन आज किसी भी अन्य बंदी सेटिंग की तुलना में अभयारण्यों में रहने वाले चिम्पांजी की संख्या अधिक है। चिम्पांजी जंगल में 45 वर्ष तक तथा कैद में 60 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शिशु चिम्पांजी को उनके छोटे आकार तथा उनकी पीठ पर सफेद बालों के गुच्छे से पहचाना जा सकता है, जो किशोरावस्था में पहुंचने पर गायब हो जाते हैं। चिम्पांजी फलभक्षी होते हैं, जिसका मतलब है कि उनका मुख्य भोजन फल है। वे पत्ते, मेवे, बीज, पक्षियों के अंडे और कीड़े भी खाते हैं। चिम्पांजी के कुछ समूह कोलोबस बंदरों और अन्य छोटे स्तनधारियों का शिकार करके उन्हें खाते हैं।

डॉ. जेन गुडॉल ने 1960 में जंगली चिम्पांजी द्वारा औजारों के इस्तेमाल की खोज की थी, जब उन्होंने एक चिम्पांजी को दीमक के टीले से दीमक निकालने के लिए घास के पत्तों का इस्तेमाल करते देखा था। चिम्पांजी को अखरोट तोड़ने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते और मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने के लिए छड़ियों का इस्तेमाल करते भी देखा गया है। रात में, चिम्पांजी पेड़ों पर सावधानी से चुनी गई शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करके सोने के लिए घोंसले बनाते हैं। चिम्पांजी इशारों, चेहरे के भावों और आवाजों का उपयोग करके संवाद करते हैं। वे गले लगकर, हाथ छूकर और यहाँ तक कि चूमकर एक-दूसरे के प्रति स्नेह दिखाते हैं। खेलते समय चिम्पांजी हँसते हैं।

विश्व चिम्पांजी दिवस हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चिम्पांजी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यह दिन डॉ. जेन गुडॉल के 1960 में तंजानिया के गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में जंगली चिम्पांजी का अध्ययन करने के लिए पहली बार जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। चिम्पांजी हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। वे वनों की कटाई, अवैध शिकार, और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। विश्व चिम्पांजी दिवस इन शानदार प्राणियों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी जेन गुडाल ने तंजानिया में उनके साथ दशकों तक रह कर उनका अध्ययन किया। उन्हें जीवित जानवरों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। वे समस्याओं को हल कर सकते हैं, उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास एक जटिल संचार प्रणाली है। शिशु चिम्पांजी की तस्वीरें वास्तव में प्यारी हो सकती हैं। चिम्पांजी खतरनाक हो सकते हैं। चिम्पांजी

जंगल में बंदरों को मारने और खाने के लिए समूहों में शिकार करेंगे। यह खतरनाक लग सकता है, लेकिन वे जंगली जानवर हैं। कई अन्य जानवर शिकार को मारने के लिए समूहों में शिकार करते हैं, खासकर मांसाहारी जो जीवित रहने के लिए मांस पर निर्भर होते हैं। शेर, भेड़िये और लकड़बग्घे सभी झुंड में शिकार करते हैं और अपने शिकार को मारते और खाते हैं। चिम्पांजी इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें खतरा महसूस हो या वे अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हों।

चिम्पांजी लोगों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वे आम तौर पर इंसानों से बचते हैं। जंगली चिम्पांजी और पालतू जानवरों के रूप में पाले जाने वाले चिम्पांजी द्वारा इंसानों पर हमला करने के मामले दर्ज किए गए हैं। जंगली चिम्पांजी की तुलना में पालतू



चिम्पांजी द्वारा हमला करने के मामले ज्यादा हैं। जंगल में चिम्पांजी अपने आवास के नुकसान के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। उन्हें अधिक मानवीय संपर्कों का सामना करना पड़ता है, जिससे झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। दर्ज की गई अधिकांश दुर्घटनाएँ मनुष्यों पर हमला करने वाले चिम्पांजी के समूह की नहीं थीं, बल्कि अकेले चिम्पांजी की थीं, जो शायद भोजन के लिए बेताब थे, जिन्होंने मनुष्यों को मार डाला। पालतू चिम्पांजी ने भी इंसानों पर हमला किया है। ट्रैविस नामक नर चिम्पांजी का एक बेहद चर्चित मामला, जिसे सैंड्रा हेरोल्ड ने पाला था, ने जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सैंड्रा हेरोल्ड ने उसे तब से पाला था, जब वह तीन दिन का था और वह अपने मालिक और उसके परिवार के साथ कई सालों तक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसने विज्ञापनों में कुछ जानवरों की भूमिकाएँ भी निभाई और टीवी शो में भी दिखाई दिया। दुर्भाग्य से 16 फरवरी, 2009 को चिम्पांजी ने सैंड्रा से मिलने आई एक महिला पर हमला कर दिया। ■

सारंडा की यह नीरवता मन को अस्थिर करती है

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव जब एकीकृत बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और गिरिराज सिंह प्रदेश के महामंत्री थे, मैं पश्चिम सिंहभूम के प्रभारी के नाते संगठन का काम देख रहा था। युवा मोर्चा के मेरे अभिन्न मित्र स्वर्गीय गुंजन मछुआ जी के साथ सारंडा क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का आकलन करने हेतु सघन दौरा किया था।

■ सुबोध श्रीवास्तव

सारंडा जंगल को उस समय सूर्य की किरणें भेद नहीं पाती थीं। वन्यजीव अक्सर दिखलाई पड़ते थे। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ पत्तों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती थी। जनजातियों के गांव वन्य-संस्कृति के आवरण को ओढ़े हुए थे। झरझर की आवाज से कारों और कोईना नदी की बीच जंगल से कलकल की आवाज रोमांचित करती थीं। यही थी सारंडा के जल जंगल और जमीन की परिभाषा, जिसके नाम पर केवल अर्थ दोहन और जनजातियों के नाम पर राजनीति होती रही।

सारंडा पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक अत्यंत घना, जैवविविधता से समृद्ध एवं खनिज संपदा से भरपूर जंगल है। यह क्षेत्र भारत के सबसे घने साल वृक्षों के जंगलों में से एक है। इसका ऐतिहासिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है।

सारंडा शब्द का अर्थ है साल के सात सौ पहाड़। यह क्षेत्र साल के वृक्षों और पहाड़ी भू-आकृति के लिए जाना जाता है। यह जंगल भारत-ओडिशा सीमा के निकट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र हो जनजाति और अन्य आदिवासी समुदायों का निवास क्षेत्र रहा है, जिनकी संस्कृति, पूजा-पद्धतियां एवं जीवन-शैली प्रकृति पर आधारित रही हैं। आदिवासी समाजों में यह जंगल पवित्र माना जाता रहा है। यहाँ अनेक पवित्र उपवन भी मिलते हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय सारंडा जंगल को रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। अंग्रेजों ने यहाँ वनों के दोहन और खनिज उत्खनन की शुरुआत की। साथ ही रेलवे लाइन बिछाई गई जिससे जंगलों से लकड़ी और खनिज बाहर ले जाया जा सके। वन्यजीव में हाथी, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, विभिन्न प्रकार के पक्षी, साँप की बहुलता थी। यह जंगल सारंडा एलिफेंट रिजर्व का भी

हिस्सा है, जो हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर (मार्ग) है।

आदिवासी समाज और संस्कृति से जुड़ी जनजातियां मुंडा, भील, और कुछ क्षेत्रों में संथाल भी निवास करती हैं। इनकी जीविका वनोपज, कृषि, शिकार और हाल के वर्षों में खनन उद्योग से जुड़ी मजदूरी पर आधारित है। इनका जीवन जंगल से जुड़ा है। भोजन, औषधि, ईंधन, पूजा सामग्री सब जंगल से ही आता है।

खनिज संपदा: यह क्षेत्र लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार है। भारत की कई बड़ी खनन कंपनियाँ जैसे सेल, टाटा स्टील समेत कई निजी कंपनियाँ यहाँ सक्रिय हैं।

खनन का कुप्रभाव: पर्यावरणीय क्षति तेजी से हुई है। वनों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना, जैवविविधता में कमी आना प्रमुख है। पारंपरिक निवास से जनजातियों का विस्थापन भी पर्यावरणीय संक्रमण का हिस्सा है। खनन के कारण उत्पन्न स्थानीय आक्रोश, आंदोलनों का जन्म हुआ जो इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। जनजातियों की उपेक्षा, रोजगार के नाम पर केवल दोहन एवं जनसुविधाओं की घोर कमी के कारण 2000 के दशक में सारंडा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गया। 2011 में भारत सरकार ने इसके विरुद्ध अभियान चलाकर इसमें कमी लाने का प्रयास भर किया। जंगलों की दुर्गमता और सरकारी उपेक्षा ने नक्सलियों को पनपने का अवसर प्रदान करता रहा है।

सारंडा एक्शन प्लान के तहत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की सुविधा, और आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई गई। इससे कुछ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, परंतु कई गाँव अब भी बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं से वंचित हैं। खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष आज भी जारी है। कई एनजीओ और पर्यावरण संगठन यहाँ सतत विकास और जंगल की रक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। इसमें युगांतर भारती जैसी संस्थाएं भी भूमिका निभा रही हैं। अनियंत्रित खनन और वनों की कटाई जैसी कठिन चुनौतियां कायम हैं। आदिवासी अधिकारों की अनदेखी आम है। पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब भी दिखाई दे रहा है। सारंडा से प्रेम करने के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। सतत खनन नीति के तहत विकास और पर्यावरण का संतुलन धरातल पर दिखना चाहिए एवं इसकी निगरानी और मैप का निर्धारण निश्चित अंतराल में किया जाना जरूरी समझा जाए। जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है।

सारंडा जंगल झारखंड का हरा फेफड़ा है, जो केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक संस्कृति, इतिहास, संघर्ष और आशा का प्रतीक है। यह जंगल हमें यह सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें प्रकृति, संस्कृति और समाज के बीच संतुलन बना रहे।

प्रकृति का मौन क्रंदन

स घन सारंडा जंगल कभी प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग था। सघनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हरे-भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ और असीम शांति—यह जंगल न केवल जैव विविधता का खजाना था, बल्कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत उदाहरण था।

सारंडा जंगल कभी हो, मुंडा और उरांव आदिवासी समुदायों के लिए जीवनदायिनी धरोहर था। यहाँ की मिट्टी से उनका गहरा नाता था। जंगल उन्हें न केवल भोजन, औषधियाँ और लकड़ी देता था, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता था। पर्व-त्योहारों में जब ढोल-नगाड़ों की गूंज जंगल की गहराइयों में गूंजती थी, तब संपूर्ण क्षेत्र में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। इस जंगल में हाथियों के झुंड सहजता से विचरण करते थे। जंगली बिल्लियाँ, तेंदुए, और असंख्य पक्षियों की प्रजातियाँ इसे एक जीवित जैव-विविधता संग्रहालय बनाती थीं। यह सिर्फ एक जंगल नहीं था—यह एक साँस लेता हुआ, धड़कता हुआ अस्तित्व था।

वर्तमान की विडंबना ये है कि समय की आंधियों ने सारंडा जंगल की इस पहचान को धीरे-धीरे मिटा दिया। खनिजों की लोलुपता, अवैध कटाई और बेतरतीब विकास ने इस जंगल को बुरी तरह झकझोर दिया है। जहाँ कभी पगडंडियों पर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, वहाँ अब भारी मशीनों की गर्जना है।

आज सारंडा जंगल सिकुड़ता जा रहा है। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास से उजड़ रहे हैं। हाथियों और इंसानों के बीच टकराव आम हो गए हैं। हाथियों का दिखना नगण्य सा ही है। पर्यावरणीय असंतुलन ने न केवल जैव-विविधता को खतरे में डाला है, बल्कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली भी संकट में है।

सारंडा जंगल आज मौन है, परंतु उसकी हर सूखी डाल, हर मुरझाया हुआ पत्ता, हर दम तोड़ती नदी एक सन्देश दे रही है—मुझे बचाओ। यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी प्रकृति की आत्मा है। हमें यह समझना होगा कि जंगल को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा है। सारंडा को फिर से हरियाली से लहलहाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसकी छाँव में साँस ले सकें।

सारंडा का अतीत हमें गौरव देता है और वर्तमान हमें चेतावनी। यह समय है जब हम सभी मिलकर इसे फिर से संजीवनी देने का प्रयास करें। वरना वह दिन दूर नहीं जब इतिहास की किताबों में सिर्फ एक जंगल रह जाएगा...जो कभी जीवित था। ■



बाघों के दुश्मन

■ आशुतोष मिश्रा

कभी गूंजती थी दहाड़, वहां है सन्नाटा

आखिर कहां गया भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ?

भारतीय उपमहाद्वीप के घने वनों में बाघ आज अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। इतिहास साक्षी है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना में बाघ केवल वन्य प्राणी नहीं, बल्कि शक्ति, तेज और साहस का प्रतीक रहा है। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, प्रतीकचिह्नों, साहित्य, लोककथाओं और देवी-देवताओं के वाहनों में बाघ का स्थान सर्वोच्च रहा है। किन्तु विडम्बना है कि यही बाघ आज मनुष्य की महत्वाकांक्षा, लोभ और उपेक्षा का शिकार बन गया है।

क्यों

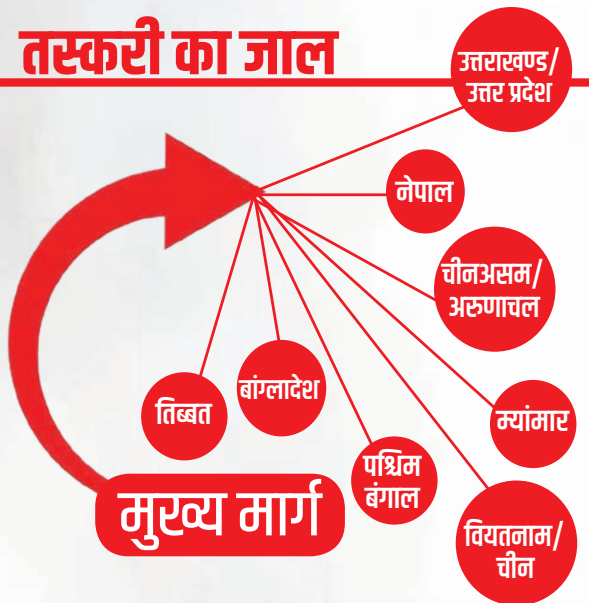
बाघ संकट में हैं? उनका दुश्मन कौन है? क्या यह केवल शिकारियों की बंदूकें हैं, या कुछ और भी? क्या कानून और संरक्षण नीतियां पर्याप्त हैं? आखिर किसके लिए बाघों की खाल, हड्डियां और नाखून 'सोने से भी कीमती' बन गई हैं? इस कवर स्टोरी में हम बाघों के अस्तित्व पर मंडराते हर खतरे की परतें खोलेंगे - आंकड़ों, साक्ष्यों, मानव-प्रेरित लालच और संरक्षण प्रयासों की सच्चाई के साथ।

बाघों का 'अदृश्य युद्ध'

भारत में एक समय बाघों की संख्या लगभग चालीस हजार थी। किंतु आज तीन हजार से अधिक होना एक 'मील का पत्थर' माना जा रहा है। तस्कर गिरोह सुनियोजित ढंग से वनरक्षकों को चकमा देकर बाघों पर निशाना साधते हैं।

शिकार और अवैध तस्करी माफिया

तस्करी का जाल



बाघों का सबसे बड़ा दुश्मन वह है, जो सीमा पार से दिखाई नहीं देता। चीन, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड जैसे देशों में बाघ के शरीर का प्रत्येक अंग बहुमूल्य है। खाल वहां दीवारों पर टंगी रहती है। बाघ की हड्डियां शराब में घोली जाती हैं। दांत और नाखून ताबीज बनते हैं। पित्ताशय और लिंग से तथाकथित यौन शक्ति वर्धक दवाइयां बनाई जाती हैं। बाघ वहां सौंदर्य नहीं, व्यापार है। कीमत है—लाखों रुपये। यही लोभ भारत में तस्करों को खींच लाता है।

बाघों का इस्तेमाल कहां और कैसे होता है?

बाघ एक "करेंसी" बन चुके हैं - खासकर काले बाजारों में। आइए देखें बाघ के किस हिस्से की क्या उपयोगिता है:

- » अंग उपयोग और मुख्य देश
- » खाल फर्श, कोट, प्रदर्शन-चीन, नेपाल और तिब्बत में
- » हड्डियां पारंपरिक दवाइयां, बाघ वाइन-चीन और वियतनाम में
- » नाखून/दांत गहनों, ताबीजों में उपयोग-थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में
- » लिंग/लिवर आदि यौन शक्ति बढ़ाने के लिए (झूठे दावे)-चीन और कोरिया में
- » एक बाघ से मिलने वाले अवयव की औसत काले बाज़ार में कीमत: 10-15 लाख रुपये
- » नेपाल व म्यांमार सीमाओं पर तस्करी की वार्षिक घटनाएँ: 200 से ज्यादा
- » भारत में तस्करी रोधी टीमों की संख्या: सीमित और अधिशेष

उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल से नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं के रास्ते बाघ के अवशेषों का काला व्यापार हर वर्ष जारी है। कैमरे, सेंसर, गश्ती दल-सभी बेबस हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2022 तक 3,377 बाघों के अवशेष जब्त किए गए। यह लगभग हर हफ्ते एक बाघ के शिकार का प्रमाण है।

आवास का क्षरण

बाघों का विनाश केवल शिकार या तस्करी से नहीं हो रहा। उसके जीवन का हर आश्रय, हर आधार छीन लिया गया है। विशाल वन क्षेत्रों को खनन परियोजनाओं, बिजली संयंत्रों, सड़कों, रेलमार्गों और कृषि विस्तार के लिए काट दिया गया। उसके शिकार की प्राकृतिक व्यवस्था समाप्त हो गई। उसकी निर्भीकता छीन ली गई। अब वह भटकता है, भूखा है, भयभीत है। जंगल छोटा हुआ तो बाघ गांवों की ओर आया। गांवों में उसके स्वागत में विष रखे गए। जाल बिछाए गए। बंदूकें तनीं। उसने मवेशी मारे, तो गांववालों ने उसे मारा। यह संघर्ष दोनों के लिए घातक है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 2001 से 2020 तक लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हुआ।

क्या है कानून?

भारत में बाघ को उच्चतम संरक्षण प्राप्त है, कहने को कानून कठोर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 के अंतर्गत बाघ आता है। शिकार

पर पूर्ण प्रतिबंध है। दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और 50 हजार तक का जुर्माना (जिसे बाद में बढ़कर 25 लाख रुपये कर दिया गया)। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: प्रदूषण और जैवविविधता को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई।। प्रोजेक्ट टाइगर योजना ने 50 से अधिक बाघ अभयारण्य बनवाए। करोड़ों रुपये खर्च हुए। फिर भी बाघ असुरक्षित हैं क्योंकि जंगल से बाहर उसकी रक्षा की दीवारें कमजोर हैं। सीमाओं पर निगरानी शिथिल है। तस्कर आधुनिक हैं, वन रक्षक पुराने। सच तो यह है कि केवल कानून होने से बाघ नहीं बचते। सख्त निगरानी, राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जनता की भागीदारी जरूरी है।

वर्ष	अनुमानित बाघों की संख्या (भारत)
1900	40,000
1972	1,827
2018	2,967
2023	3167

नया खतरा: कृत्रिम पालन केंद्र

चीन, लाओस तथा वियतनाम में पिंजरे में पाले गए बाघों की मृत्यु के पश्चात उनके अंगों का व्यापार सुनिश्चित करने हेतु खोल दिए गए 'बाघ पालन केंद्र' अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। इससे भारत में भी ऐसे केंद्रों की खुले तौर पर मांग बढ़ सकती है।

चुनौतियां

हर तरफ निराशा ही नहीं है। आशा की किरणें भी हैं। कैमरा ट्रैप तकनीक से बाघों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। 'बाघ गलियारे' बनाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकें। जिम कार्बेट जैसे क्षेत्रों में 'दृष्टि-नेत्र परियोजना' से सीधी निगरानी शुरू हुई है। कुछ गाँवों में स्थानीय लोगों को बाघ संरक्षण का मित्र बनाया गया है। लेकिन यह प्रयास बूँद-बूँद हैं। समुद्र बनने में अभी काफी देर है।

आम जनता की भूमिका

अब समय आ गया है कि हम सब बाघ संरक्षण के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। यदि आपके क्षेत्र में वन्यजीवों की अवैध तस्करी या शिकार हो रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन को दें। कृपया कभी भी वन्य जीवों के अंगों से बने उत्पाद न खरीदें, न इनके व्यापार को प्रोत्साहन दें। बाघ केवल वन्यजीव नहीं, सम्पूर्ण जैविक श्रृंखला का प्रमुख आधार है। यदि हम बाघ को बचाते हैं, तो अपनी जलवायु, अपनी नदियाँ, अपनी हरियाली, अपने भविष्य को बचाते हैं।

स्थानीय संरक्षण समितियों में भागीदारी

बाघों को बचाना केवल एक प्रजाति को बचाने की बात नहीं है -यह पूरे



**जहां बाघ की
आखिरी गर्जना
थमती है, वहां जीवन
की धड़कनें भी थम
जाती हैं।**

पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने का प्रयास है। जहां बाघ रहता है, वहां जंगल होता है और जहां जंगल होता है, वहां जीवन की शुद्धता होती है। बाघों के दुश्मनों की सूची लंबी है -शिकारियों से लेकर लालची उपभोक्ताओं तक, माफिया से लेकर निष्क्रिय अधिकारियों तक। लेकिन इन दुश्मनों से बड़ा दुश्मन है- हमारी उदासीनता। यदि हम बाघों के लिए नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां केवल ग्रंथों में उसकी गर्जना सुनेगी। समय है-चेतने का, बचाने का, साथ चलने का। क्योंकि बाघ बचेगा, तो देश बचेगा। याद रखें-बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा। यही भारत का भविष्य है।

(नोट: यह समझने की जरूरत है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय पशु शेर। लेकिन, नए-पुराने अध्ययनों में इस बात को गहराई से देखा/कित किया गया है कि कहने को भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है, लेकिन असल में शेर तो बाघ ही है। बाघ हमेंशा से शेर से ज्यादा ताकतवर रहा है। इसलिए किसी भ्रांति में न फंसें। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर भले ही कहा जाए, असली राजा तो बाघ ही है।)



पहले से तो बेहतर है बाघों की स्थिति

भारत में बाघों की स्थिति अब पहले से बेहतर है। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 3,682 है, जो 2018 में 2,967 थी। यह वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 75% है। यह सही है कि 2006 से 2022 के बीच भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा वर्ष 1900 में भारत में बाघों की संख्या 40,000 से भी ज्यादा थी। यह सत्य है कि संख्या में

जबरदस्त कमी हुई है, फिर भी आज जो बाघों की संख्या है, वह संतोष करने लायक है क्योंकि भारत में दुनिया के 75% से अधिक बाघ पाए जाते हैं। वैसे बाघों की संख्या में वृद्धि का श्रेय मजबूत संरक्षण रणनीति और बाघों के लिए सुरक्षित आवास क्षेत्रों के निर्माण को दिया जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। झारखंड में 5 बाघों की संख्या सदैव से बताई जाती रही है। अभी भी 5 बताई जा रही है। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे परियोजना ने बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी कार्यरत है जो बाघों के संरक्षण के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाघों की निगरानी के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम, बाघों की सुरक्षा और उनके आवास की निगरानी में मदद करता है। बाघों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। दरअसल, भारत में बाघों की स्थिति में सुधार एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन बाघों को अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है। अवैध शिकार, आवास का नुकसान और जलवायु परिवर्तन बाघों के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। हमें यह मान कर चलना होगा कि बाघों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें थोड़ी सी भी ढील नाकाबिले बर्दाश्त है। ■



भारत में रहते हैं 70 फीसदी से अधिक बाघ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक, बाघों की आबादी की अधिकतम सीमा 3,925 होने का अनुमान है, जिसमें औसतन 3,682 बाघ हैं।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

हर साल 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। भारत, जहां दुनिया की 70 फीसदी से अधिक बाघ आबादी रहती है, यहां कुछ बेहतरीन बाघ अभयारण्य भी हैं। साथ ही यह दिन इन जानवरों के समक्ष आने वाले खतरों जैसे अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इन सब पर गौर करने का भी दिन है। इस साल वन्यजीव अपराध से निपटने, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने, स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और बाघों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयासों को तेज किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के

दौरान की गई थी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (जीटीआई) द्वारा किया गया था, जिसमें बाघ संरक्षण के लिए समर्पित राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संरक्षण समूह शामिल हैं। टाइगर रेंज कंट्रीज (टीआरसी), जंगली बाघ आबादी वाले देश, दुनिया भर में बाघों की संख्या में भारी गिरावट से निपटने के लिए एकत्र हुए।

इन शानदार बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए समन्वित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, टीआरसी ने बाघ संरक्षण और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल एक दिन समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के लिए चुना, जो शिखर सम्मेलन के पहले और आखिरी दिनों के बीच का मध्य बिंदु है, जो बाघों को बचाने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयास का प्रतीक है।

दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित बड़ी बिल्लियां या बाघ गंभीर



शुरु हो गई बाघों की गिनती

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में पूरे देश में बाघों की गिनती शुरू होने जा रही है। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार का इलाका बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। तीनों जिलों में पलामू टाइगर रिजर्व मौजूद है जो बाघों के लिए मशहूर है।

दरअसल, बाघों की गिनती का आंकड़ा हर चार साल में जारी किया जाता है। बाघों की गिनती का काम दो साल तक चलता है और 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे पर बाघों का आंकड़ा जारी किया जाता है। बाघों की गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण में मास्टर ट्रेनरों को गिनती से संबंधित जानकारी दी गई। बाद में टाइगर रिजर्व के इलाके में तैनात जवानों को गिनती के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। यह गिनती गत मई माह से ही शुरू है।

पीटीआर के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना कहते हैं: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो साल तक चलेगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगुवाई में देशभर के टाइगर रिजर्व के निदेशकों और उपनिदेशकों की बैठक दिल्ली में हुई थी। उसी में बाघों की गिनती के संबंध में फैसला हुआ।

बाघ गिनती के दौरान पूरे पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 550 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है, समय-समय पर कैमरे का स्थान बदलता

बाघ गिनती के दौरान पूरे पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 550 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है, समय-समय पर कैमरे का स्थान बदलता रहेगा।

रहेगा। इस दौरान बाघों के विचरण वाले क्षेत्र में स्कैट का संग्रह भी रखा जाएगा। बाघों के विचरण से जुड़ा हर डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। सारा डेटा भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजा जाएगा।

1973 में शुरू हुई थी बाघों की गिनती

1973 में देश भर में 09 बाघ रिजर्व बनाए गए थे। इन नौ बाघ रिजर्व में पलामू टाइगर रिजर्व भी शामिल था। भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2023 की रिपोर्ट में पलामू टाइगर रिजर्व किला में बाघों की संख्या चार बताई गई थी। 2018 की रिपोर्ट में पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी। पिछले डेढ़ साल में पलामू टाइगर रिजर्व में छह बाघों की चहलकदमी दर्ज की गई है। ■

खतरों का सामना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन, सभी क्षेत्रों के लोग बाघ संरक्षण की तत्काल जरूरत पर जोर देने के लिए एक साथ आते हैं। इन शानदार जानवरों को आवास विनाश, अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव तस्करी से खतरा है, जो उन्हें विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक समर्थन जुटाने और बाघों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी पहल को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। बाघ संरक्षण में अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, इस दिन का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करना है।

भारत में बाघों की संख्या

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के पांचवें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कम से कम 3,167 बाघ हैं और अब यह दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 70 फीसदी से अधिक का घर है। वैसे, बाघों की नए सिरे से गिनती प्रारंभ हो गई है जिसकी रिपोर्ट 2027 में आएगी।

कैमरे में कैद और बिना कैमरे के बाघ उपस्थिति क्षेत्रों के लिए नवीनतम सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करके आगे के आंकड़ों के विश्लेषण से बाघों की आबादी की अधिकतम सीमा 3,925 होने का अनुमान है, जिसमें औसतन 3,682 बाघ हैं, जो 6.1 फीसदी की सराहनीय वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से की गई अग्रणी पहलों के कारण यह उल्लेखनीय संरक्षण उपलब्धि हासिल की गई है। ■



नदियों में बह रहा धीमा जहर

जो नदियां कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, वो आज इंसानी लालच और लापरवाहियों की वजह से पारे से भरती जा रही हैं। इस पर प्रकाश डालने के लिए तुलाने विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने दुनिया की नदियों में पारे की मात्रा पर एक नया अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चला है कि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में आज दुनिया की नदियों में पारे का स्तर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। पारा एक ऐसा धीमा जहर है जो न सिर्फ जलजीवों, बल्कि इंसानों के दिमाग तक को नुकसान पहुंचा रहा है। अध्ययन के मुताबिक, 1850 से पहले नदियां हर साल करीब 390 मीट्रिक टन पारा समुद्रों तक पहुंचाती थी। लेकिन अब यह मात्रा बढ़कर सालाना करीब 1,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने ये आंकड़े नदियों में पारे की आवाजाही को समझने के लिए तैयार एक मॉडल के जरिए जुटाए हैं।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क



अमेरिका के तुलाने विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं। अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मोसार्ट एचजी नामक एक खास कंप्यूटर मॉडल की मदद ली है। यह मॉडल औद्योगिक काल से पहले जमीन से नदियों के जरिए समुद्रों तक पहुंचने वाले पारे की मात्रा का आकलन करता है। इस मॉडल से मिले नतीजे दुनियाभर के तटीय इलाकों से लिए गए पुराने तलछट के नमूनों में मिले पारे के स्तर से काफी मेल खाते हैं, जोकि अध्ययन की सटीकता की पुष्टि करते हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें सीवेज और गंदे पानी का सीधे नदियों में छोड़ा जाना, मिट्टी का कटाव और उद्योगों व खनन से निकलने वाला पारा है। तुलाने विश्वविद्यालय के अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर यान्शू झांग के मुताबिक, “मानव गतिविधियों ने पारे के वैश्विक चक्र को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।

पहले के शोधों में हवा, मिट्टी और समुद्र पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन नदियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वे अब पारे के बहाव की मुख्य धार बन चुकी हैं।”

इस अध्ययन के नतीजे इंसानों और वन्यजीवों दोनों के लिए गंभीर खतरे का संकेत देते हैं, क्योंकि पारे के यौगिक एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। ये मछलियों में जमा हो सकते हैं, जिनके सेवन से इंसानों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में जानकारी दी है कि पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में पक्षियों के प्रवास

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें सीवेज और गंदे पानी का सीधे नदियों में छोड़ा जाना, मिट्टी का कटाव और उद्योगों व खनन से निकलने वाला पारा है। तुलाने विश्वविद्यालय के अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर यान्शू झांग के मुताबिक, “मानव गतिविधियों ने पारे के वैश्विक चक्र को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।

मार्गों के पास बहने वाली नदियों में पारे का स्तर तेजी से बढ़ा है जोकि बेहद चिंताजनक है।

शोधकर्ता झांग के मुताबिक औद्योगिक युग से पहले नदियों में पाए जाने वाले पारे के स्तर को एक आधार माना जा सकता है। उनके अनुसार, यह आंकड़ा मिनामाता कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए लक्ष्य तय करने में मददगार हो सकता है, जिनका मकसद दुनियाभर में पारे के प्रदूषण को कम करना है।

अध्ययन से पता चला है कि 1850 के बाद नदियों में पारे के प्रदूषण में सबसे तेज बढ़ोतरी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1850 से अब तक दुनिया में जितना पारा बढ़ा है, उसका 41 फीसदी वहीं से आया है। इसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया में 22 फीसदी और दक्षिण एशिया 19 फीसदी के योगदान के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पारंपरिक और छोटे पैमाने पर किया जाने वाला सोने का खनन पारे के बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। खासकर अमेजन क्षेत्र में जंगलों की कटाई से होने वाला मिट्टी कटाव और खनन गतिविधियों से निकला पारा, नदियों में पारे का स्तर तेजी से बढ़ा रहा है।

अध्ययन से पता चला है कि अमेजन नदी में अब हर साल 200 मीट्रिक टन से ज्यादा पारा पहुंच रहा है, जिसमें से करीब 75 फीसदी के लिए इंसानी गतिविधियों जिम्मेवार हैं। इनमें भी सोने के हो रहे खनन की बड़ी भूमिका है। वहीं पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में पारे के बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह उद्योगों से निकलने वाला पारा है। खासकर चीन की नदियां इस क्षेत्र में 70 फीसदी से ज्यादा पारा ला रही हैं। यांग्त्ज़ी नदी में पारे का प्रवाह औद्योगिक काल से पहले के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा हो गया है।

हालांकि दुनिया के सभी क्षेत्रों में पारे का स्तर नहीं बढ़ा है। भूमध्यसागर क्षेत्र में औद्योगिक काल से पहले की तुलना में अब पारे की मात्रा कम पाई गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इसकी वजह नील नदी पर अस्वान हाई डैम जैसे बड़े बांध हैं, जो पारे से भरी तलछट को रोक लेते हैं और उसे समुद्र तक नहीं जाने देते।

वैज्ञानिकों का मानना है कि नदियों में पारे का स्तर एक मापक बन सकता है। इससे यह तुरंत आंका जा सकता है कि पारे को रोकने के लिए देशों की कोशिशें कितनी असरदार हैं और प्रदूषित इलाकों को सुधारने में उन्हें कितनी कामयाबी मिल रही है। ■

झारखंड सरकार के प्रयास और वृक्ष कटाव रोकने की पहल

हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो हमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की महत्ता को याद दिलाता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध जैव-विविधता, घने जंगलों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यह राज्य प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। झारखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष कटाव को रोकने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में योगदान दे रही हैं। इस लेख में, हम झारखंड सरकार द्वारा प्रकृति संरक्षण और वृक्ष कटाव रोकने के लिए किए गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इन प्रयासों के प्रभाव और चुनौतियों का भी विश्लेषण करेंगे।

■ एस. विद्यासागर

झारखंड: प्रकृति का खजाना

झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगलों का देश, अपने घने जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहां के पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जैसे क्षेत्र जैव-विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि औद्योगीकरण, खनन और अवैध वृक्ष

कटाई जैसे कारकों ने राज्य के पर्यावरण को खतरे में डाला है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए झारखंड सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जो प्रकृति संरक्षण और वृक्ष कटाव रोकने में मदद कर रहे हैं।

वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

झारखंड सरकार ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो

और वन आच्छादन बढ़े। इसके तहत सरकार किसानों को मुफ्त पौधे, तकनीकी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए गोड्डा जिले में वन विभाग ने एक वित्तीय वर्ष में 6,63,300 पौधे लगाने और सड़कों के किनारे 20,510 पौधों को रोपने की योजना बनाई थी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार भी प्रदान करता है।

सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना

हाल ही में झारखंड सरकार ने सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना शुरू की है, जो वनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक नई पहल है। इस योजना के तहत, वैज्ञानिक तरीकों से जंगलों का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें पुराने और कमजोर पेड़ों को हटाकर नए पौधों को लगाने पर जोर दिया जाता है। यह योजना न केवल जंगलों की गुणवत्ता को सुधारती है, बल्कि वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास भी सुनिश्चित करती है।

जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण

झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने की दिशा में भी काम किया है। तालाबों और नदियों के संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, और मिट्टी के अपक्षरण को रोकने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि घने जंगलों को बचाने और मिट्टी के कटाव को रोकने से झारखंड को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है।

सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता

झारखंड सरकार ने प्रकृति संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। वृक्ष बचाओ, जंगल बचाओ जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा, वन विभाग द्वारा प्रत्येक ग्रामीण को मुफ्त में 10 पौधे प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर सकें।

पर्यावरणीय मंजूरी और वनीकरण

विकास परियोजनाओं के कारण होने वाली वृक्ष कटाई की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने वनीकरण को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए मंडल बांध परियोजना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार ने 2015 से 120 मिलियन से अधिक पौधे लगाए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बना रहे।

वृक्ष कटाव को रोकने के लिए उठाए गए कदम

वृक्ष कटाव एक गंभीर समस्या है, जो झारखंड के जंगलों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। अवैध लकड़ी कटाई और लकड़ी माफिया की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन

झारखंड सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करती है। इस अधिनियम के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। इसके अलावा, वन चेक पोस्ट (जांच नाका) स्थापित किए गए हैं, जो अवैध लकड़ी परिवहन को रोकते हैं।

पेड़ों की कटाई पर नियमन

वन विभाग के अनुसार यदि 3,000 से कम पेड़ काटे जाते हैं, तो 10 गुना पौधे लगाने का प्रावधान है, जबकि 15,000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर 5 गुना पौधे लगाए जाते हैं। यह नीति सुनिश्चित करती है कि कटाई के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाए।

पेड़ों का स्थानांतरण

विकास परियोजनाओं के दौरान पेड़ों को काटने के बजाय, सरकार ने पेड़ों के स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए रांची में एक व्यक्ति ने अपने निर्माणाधीन घर के लिए चार बड़े पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें स्थानांतरित किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम माना गया।

जंगल बचाओ आंदोलन

झारखंड में 1982 में शुरू हुआ जंगल बचाओ आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। इस आंदोलन ने आदिवासी समुदायों को अपने जंगलों को बचाने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने इस तरह के आंदोलनों को समर्थन देकर स्थानीय समुदायों को वृक्ष संरक्षण में भागीदार बनाया है।

चुनौतियां और भविष्य की राह

हालांकि झारखंड सरकार ने प्रकृति संरक्षण और वृक्ष कटाव रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण के बाद पौधों की देखभाल और सिंचाई की कमी के कारण कई पौधे सूख जाते हैं। इसके अलावा, अवैध लकड़ी कटाई और लकड़ी माफिया की गतिविधियां पूरी तरह से रुक नहीं पाई हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को ये कदम उठाने चाहिए

निगरानी तंत्र को मजबूत करना: ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके अवैध कटाई पर नजर रखी जा सकती है।

जल संरक्षण पर जोर: नए पौधों की सिंचाई के लिए जल संरक्षण योजनाओं को और प्रभावी करना होगा।

सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना: स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण में और अधिक सक्रिय भूमिका दी जानी चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता: स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। ■



पर्यावरण को बचाने वाले

जंगलों की प्रहरी 'लेडी टार्जन' जमुना टुडू



जंगलों को बचाने की लड़ाई को जनआंदोलन में बदलने वाली पूर्वी सिंहभूम की जमुना टुडू आज देशभर में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी हैं। 42 वर्षीय जमुना ने 18 साल की उम्र में जंगल माफिया के खिलाफ तीर-धनुष उठाया था। अब उनकी अगुआई में 10,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो वन सुरक्षा समिति के तहत बांस, भाले, धनुष-बाण लेकर जंगलों में गश्त करती हैं। 'लेडी टार्जन' के नाम से मशहूर जमुना का जन्म 19 दिसंबर 1980 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में हुआ। विवाह के बाद 1998 में जब वह झारखंड के मुतुरखम आई, तो उन्होंने गांव के पास अवैध पेड़ कटाई का विरोध किया और संरक्षण की मुहिम छेड़ी। उनकी बहादुरी और पर्यावरण के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें 2014 में गॉडफ्रे फिलिप्स बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें पद्मश्री मिला। हाल ही में यूपनडीपी की 'इंस्पायरिंग इंडिया' पत्रिका में उनकी कहानी प्रकाशित की गई। जमुना टुडू का मानना है कि प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी निःस्वार्थ पहल आज पूरे देश में पर्यावरण चेतना की मिसाल बन गई है। ■

झारखंड केसरी मनोज दांगी ने पेड़ों को बनाया भाई

कोडरमा के निवासी मनोज दांगी आज झारखंड में पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरक छवि बन चुके हैं। राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के सचिव रहते हुए वे 2004 से वन्यजीव और वनों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सबसे अनोखी पहल रही पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा, जिसे अब वन रक्षा बंधन के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम में महिलाएं पूजा की थाली लेकर पेड़ों की आरती करती हैं और उन्हें राखी बांधकर उनके संरक्षण की शपथ लेती हैं। मनोज दांगी की अगुआई में रांची, खूंटी, गुमला, दलमा और गिरिडीह जैसे जिलों में हरित पदयात्रा और साइकिल यात्रा का आयोजन हुआ है। खासकर गुमला के 83 गांवों में घूम-घूमकर उन्होंने वन संरक्षण का संदेश दिया, जिससे शिकार जैसी प्रथा पर काफी हद तक रोक लगी है। ■



झारखंडी हीरोज को जानें



हरियाली के हमराही धर्मेन्द्र नारायण

धर्मेन्द्र नारायण लाल सीआरपीएफ में बतौर आला अधिकारी कार्यरत हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक अनुशासित अफसर की नहीं, बल्कि एक प्रकृति प्रेमी और हरियाली के संरक्षक की भी है। वे जहां भी तैनात हुए, वहां हरियाली की छाप छोड़ दी। धुर्वा स्थित सैंबू कैंप इसका जीवंत उदाहरण है, जहां उनके नेतृत्व में अब तक 15,000 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। कैंप परिसर में हर कोना हरियाली से भरा हुआ है। फूलों की महक, पौधों की हरियाली और वृक्षों की छांव वहां का माहौल ही बदल देती है। धर्मेन्द्र का मानना है कि पेड़ लगाना पहला कदम है। असली काम है उसकी देखभाल करना और उसे जीवित रखना। वे हर साल मानसून से पहले वृक्षारोपण की विस्तृत योजना बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पूरा परिसर हरियाली में ढक जाए। उनकी यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है, बल्कि उनके मातहतों और आसपास के लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देती है। धर्मेन्द्र नारायण आज के समय में उन चुनिंदा अफसरों में हैं, जो वर्दी के साथ प्रकृति के प्रहरी भी हैं। ■

अखिलेश अंबष्ठ ने घर को बना दिया हरियाली का मंदिर

रांची के कांके निवासी और झारखंड रेरा में निजी सहायक के पद पर कार्यरत अखिलेश अंबष्ठ ने अपने घर को प्रकृति के छोटे से जंगल में तब्दील कर दिया है। एक किसान परिवार में पले-बढ़े अखिलेश ने पेड़-पौधों के प्रति अपने लगाव को जीवन का मिशन बना लिया। आज उनके आवास में 14,000 से अधिक गमले हैं, जिनमें पीपल, कल्पतरु, रुद्राक्ष, चंदन जैसे दुर्लभ और औषधीय पौधे शामिल हैं। उनके पास 25 साल पुराने वृक्ष भी हैं, जो उनकी सतत सेवा भावना का प्रतीक हैं। वे पहाड़ी मंदिर परिसर में भी अब तक लगभग 200 पौधे लगा चुके हैं। अपने मोहल्ले में 500 से ज्यादा पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। वे पौधे निःशुल्क वितरित करते हैं और हर एक पौधे की देखभाल को अपना व्यक्तिगत दायित्व मानते हैं। पर्यावरण संरक्षण का यह भाव उन्होंने अपने परिवार में भी रोपा है। उनका बेटा कुमार अंकित आज वन्य प्राणियों की सेवा में समर्पित है। अखिलेश अंबष्ठ न केवल पेड़ लगाते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को भी हरियाली की विरासत सौंपने में जुटे हैं। वे सचमुच हरियाली के सच्चे सेवक हैं। ■



260 ब्लॉकों की यात्रा पर निकले मनमंथ वैद्य

चतरा जिले के रहनेवाले मनमंथ वैद्य ने 'जागो झारखंड यात्रा' शुरू की है, जिसका उद्देश्य है पूरे राज्य के 260 ब्लॉकों का भ्रमण कर जन-जागरूकता फैलाना। उनका यह अभियान कृषि, जल संरक्षण, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है। वे हर जगह पौधारोपण भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चतरा में 500 आम के पौधे लगाए, वहीं चाईबासा में उन्होंने दो पेड़ों से बना एक अद्भुत संयुक्त वृक्ष खोजा, जो प्रकृति की विलक्षणता को दर्शाता है। मनमंथ वैद्य का मानना है कि झारखंड की प्राकृतिक विविधता अद्वितीय और विश्व-स्तरीय है। इसे बचाना केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। उनका यह अभियान युवाओं को पर्यावरण और सामाजिक विकास से जोड़ने का प्रयास है, जो राज्य के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। प्रकृति से प्रेम और जनचेतना को साथ लेकर चल रहे मनमंथ आज झारखंड की धरती पर एक चलते-फिरते परिवर्तन-योद्धा बन चुके हैं। ■



कठोर फैसले करें, तभी मिलेगी प्लास्टिक से मुक्ति



■ चंद्रदीप पांडेय

बचपन में पढ़ी गई एक कहानी याद आती है। मुरारी नामक एक युवक किसी किसान के घर पर कार्य करता था। शाम में उसे मजदूरी के रूप में दूध मिलता था। दूध को वह अपनी माँ द्वारा उपलब्ध कराए गए कपड़े के थैले में घर लाने का प्रयास करता था। नतीजा यह हुआ कि सारा दूध बह गया। वह खाली हाथ और बेहद उदास होकर घर लौटा। थोड़ा ठहरें।

यह कहानी उस समय की याद दिलाती है, जब किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना बेहद कष्टसाध्य कार्य था। मनुष्य एक ऐसे पदार्थ की खोज में था, जो उसके दैनिक जीवन के इस प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान बन सके। फिर मानव ने एक ऐसे पदार्थ 'प्लास्टिक' का आविष्कार किया, जो उसकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम और सफल तो था किन्तु उस पर अतिशय निर्भरता उसके लिए अभिशाप बनकर अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ही तत्पर हो गई है। हिमालय की ऊँचाई से लेकर सागर की गहराई तक प्लास्टिक प्रदूषण सुरसा की भाँति मुँह बाएँ खड़ी है। वह अपने आकार का विस्तार करती जा रही है। इसे हनुमान जैसी शक्ति की बुद्धि और विवेक से ही परास्त किया जा सकता है।

आज शहर की बजबजाती नालियाँ हो अथवा अपनी उर्वरा खोते खेत, सभी के मूल में प्लास्टिक ही तो है। बड़ी संख्या में प्लास्टिक में बंधे कचरे को खाकर अपनी जान गंवाते हमारे पशुधन चीख-चीख कर हमें अपने दायित्वों के प्रति सचेष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हवा से लेकर जल और भोजन में भी प्लास्टिक के अणु घुल चुके हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

एक वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम के एक सर्वे के अनुसार, सारे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में एकत्र होता है, जिससे समुद्र का जल एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। इसका निस्तारण चुनौतीपूर्ण कार्य है। संस्था द्वारा वैश्विक स्तर पर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यह आशा बंधी है कि जिस प्रकार हम इस जादुई पदार्थ के आविष्कार में सफल हुए, ठीक उसी प्रकार हम इसके उन्मूलन में भी सफल हो पाएंगे।



समाधान क्या है?

क्या हम सरकारों के भरोसे बैठ कर अपेक्षा करें कि समाधान केवल उच्च स्तर से निकलेगा अथवा अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास व्यक्तिगत स्तर से भी प्रारम्भ कर दें? अंततः इस प्रदूषण की समस्या से प्रभावित होने वाली पहली इकाई तो हम ही हैं। अतः समग्रता से किया गया प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। अब केवल जागरूकता (Awareness) से काम नहीं चलेगा कार्रवाई (Action) करनी होगी क्योंकि कोई भी शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है।

व्यक्तिगत स्तर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं

1. **सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारना** : सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिकता में कठोर बदलाव लाकर सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे थैला (जिसे बोलचाल की भाषा में पॉलिथीन कहते हैं) सिंगल यूज बोतल, स्ट्रॉ आदि को नकारना होगा और उसके विकल्प के रूप में पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं जैसे जूट, कपड़े, मिट्टी से बनी वस्तुओं की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। ऐसा करते हुए न केवल हम प्लास्टिक को नो कह सकते हैं अपितु स्थानीय उत्पाद का उपयोग कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग कर पाएंगे।
2. **कचरा पृथक्कीकरण** : घर पर सजगता दिखाते हुए सूखे, गीले और पुनर्चक्रणीय कचरे को अलग-अलग छांट कर रखना प्रारम्भ कर दें तो न केवल इससे कचरा प्रबंधन में सहयोग मिलेगा अपितु प्लास्टिक युक्त कचरा खाने के कारण मरने वाले अनेक पशुधनों के जीवन की रक्षा हो सकेगी।
3. **पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का चयन**: अपने लिए रिसायक्लेबल, बायो डिग्रेडेबल और कोंपोस्टेबल उत्पादों का चयन कर हम पर्यावरण संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4. स्वयं को फास्ट फैशन से बचा सकते हैं। इनमें सिंथेटिक फ़ाइबर होता है जो की माइक्रो प्लास्टिक का ही एक रूप है।
5. स्वयं, परिवार तथा मित्रों के बीच जागरूकता फैलाएं। सफाई अभियान चलाएं। जन्म दिन अथवा अन्य अवसरों पर पर्यावरण अनुकूल उपहार देने की परंपरा विकसित करें।

6. अत्यधिक पैकड फूड से बचें। उसके स्थान पर घर पर बने भोजन का उपयोग कर न केवल हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं अपितु उससे होने वाले प्लास्टिक के प्रदूषण से भी बच सकते हैं।
7. विवाह /श्राद्ध/अन्य अवसरों पर होने वाली पार्टियों में प्लास्टिक से बने बर्तन के स्थान पर पारंपरिक पत्तों से बने बर्तन का उपयोग वातावरण को समृद्ध कर सकता है।

सामाजिक स्तर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं

1. अपने निवास/कार्य स्थल पर सामूहिक-साप्ताहिक स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।
2. स्थानीय नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्री तटों, पार्कों जैसे पब्लिक प्लेसेस पर स्वच्छता अभियान चलाकर विशेषकर प्लास्टिक उत्पादों को जमा कर स्थानीय निकायों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करना।
3. स्थानीय विद्यालयों में जाकर भावी पीढ़ी को प्लास्टिक के प्रदूषण से होने वाले खतरे से परिचित कराना तथा उनमें उत्तरदायित्व बोध की भावना के बीजारोपण का प्रयास करना।
4. सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर समाज को प्लास्टिक के प्रदूषण से होने वाले खतरे से आगाह करना और स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। सरकारी तंत्रों को भी आवेदन, ट्वीट्स के माध्यम से उनके दायित्व का स्मरण कराना।

औद्योगिक स्तर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं

1. उत्पादों को वर्तमान की जरूरतों और भविष्य के मानकों के अनुरूप नए स्वरूप में विकसित करें। उन्हें फिर से उपयोग करने योग्य, रिसायक्लेबल और कोंपोस्टेबल बनाएं ताकि कम लागत में अधिक लाभ मिले और प्लास्टिक प्रदूषण भी न्यूनतम हो सके।
2. जहां तक संभव हो, उत्पादों के निर्माण में वर्जिन प्लास्टिक के स्थान पर रिसायकिल्ड प्लास्टिक अथवा जैव आधारित पदार्थों का उपयोग करें



जिससे न केवल प्लास्टिक की मात्रा नियंत्रित रहेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा।

3. जमशेदपुर में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग कई स्थानों पर सड़कें बनाई गई थीं लेकिन इस पद्धति में प्लास्टिक नष्ट न होकर कुछ अवधि के बाद माइक्रो प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाती है। यह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके स्थान पर जापान में प्लास्टिक वेस्ट और रेत का उपयोग कर ईंटें बनाई गई हैं, जो सीमेंट की ईंटों से अधिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ तथा प्रदूषण शून्य होता है। औद्योगिक जगत को इस प्रकार के नए उत्पाद विकसित करना चाहिए।
4. **प्लास्टिक से ईंधन :** मूलतः प्लास्टिक में हाइड्रोकार्बन के अणु होते हैं जो जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में ताप का उत्सर्जन करते हैं। पायरोलायसिस विधि (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 6000 सेन्टीग्रेड तापक्रम पर जलाना) से प्लास्टिक वेस्ट को द्रव्य ईंधन में बदला जा सकता है। हैदराबाद की एक कंपनी ने इसका सफल उत्पादन कर डीजल से लगभग आधे कीमत पर उपलब्ध कराया है जो डीजल की तरह जलता भी है। खास यह कि यह माइक्रोप्लास्टिक की समस्या का स्थायी समाधान है।
5. हम जानते हैं कि प्रकृति किसी भी समस्या का समाधान ढूँढने में स्वयं सक्षम है किन्तु यह प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से धीमी हो सकती है। जापान ने 2016 में यह राह दिखाई है कि कुछ माइक्रो आर्गनिज्म ऐसे हैं जो पीईटी प्लास्टिक को कंज्यूम करने में सक्षम है किन्तु इसकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार के माइक्रो आर्गनिज्म के लिए एंजायम औद्योगिक स्तर पर विकसित कर प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से जड़ से निजात पाया जा सकता है।
6. औद्योगिक ईकाइयां प्लास्टिक रिडक्शन पॉलिसी और शून्य वेस्ट पॉलिसी का आंतरिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं। पैकेजिंग के लिए टेक बैक पॉलिसी और रिटेल तथा सप्लाय चैन में पर्यावरण अनुकूल पदार्थों को बढ़ावा दे सकती हैं।

सरकारी स्तर पर ये प्रयास किये जा सकते हैं

1. सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना और इस संकल्प का कठोरता से अनुपालन कराना।
2. प्लास्टिक प्रदूषण के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान और विकास कि पॉलिसी बनाना तथा इस क्षेत्र में काम करने वाली ईकाइयों, स्टार्ट-अप को सहयोग और प्रोत्साहन देना।
3. ईपीआर (एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी) को लागू करना।
4. प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो डिग्रेडेबल पदार्थों के अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक के अतिशय उत्पादन और नॉन रिसायकलेबल पैकेजिंग पर जुर्माना/भारी टैक्स आरोपित करना।
5. यूएनईए जैसी वैश्विक संस्था के प्रस्तावों और वैश्विक संधि का समर्थन करना।
6. प्लास्टिक प्रदूषण और रिसायकलिंग पर विज्ञापनों एवं अन्य माध्यमों का उपयोग कर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

आज शहर की बजबजाती नालियाँ हो अथवा अपनी उर्बरा खोते खेत, सभी के मूल में प्लास्टिक ही तो है। बड़ी संख्या में प्लास्टिक में बंधे कचरे को खाकर अपनी जान गंवाते हमारे पशुधन चीख-चीख कर हमें अपने दायित्वों के प्रति सचेष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ही थी प्लास्टिक उन्मूलन। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम भावी पीढ़ी को कैसे प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं, तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्र तट पर फैले प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन करें और जलीय जीवों को जीने योग्य वातावरण प्रदान करें। इसके साथ ही वायु और जल में घुले प्लास्टिक अणु के खतरे से जैव विविधता का संरक्षण करें तथा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से प्रकृति और मानवता को बचाएं। यदि हम प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त संकल्पों को सिद्धि में परिणत करना चाहते हैं (जो कि आवश्यक ही है) और अपने एवं अपने बच्चों के लिए जीने योग्य विश्व बनाना चाहते हैं तो हमें तत्काल कठोर निर्णय लेने ही होंगे। आत्ममुग्धता से बाहर निकालना होगा, जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा और भारतीय संस्कृति के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील संदेशों को मुखरता के साथ वैश्विक पटल पर रखना होगा। विश्व को बताना होगा कि जीने के लिए 'स्वयं' नहीं 'वयं' का सूत्र ही स्थायी और टिकाऊ समाधान है। ■

(लेखक पीएमश्री उत्कृष्ट पीपुल्स अकादमी +2 विद्यालय, न्यू बाराद्वारी, जमशेदपुर के प्राचार्य हैं)



एलएनजी से होने वाले उत्सर्जन में 60 फीसदी तक कटौती संभव

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी नई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि मौजूदा तकनीकों की मदद से तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति श्रृंखला से होने वाले ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 60 फीसदी से अधिक की कटौती की जा सकती है। गौरतलब है कि ताजा आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से होने वाले उत्सर्जन का आकलन पेश किया गया है और इसे कम करने के अहम उपाय बताए गए हैं।

■ ललित मोर्या

एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से हर साल करीब 35 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें से करीब 70 फीसदी उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जबकि बाकी 30 फीसदी मीथेन होती है, जो बिना जले ही वातावरण में पहुंच रही है। इस आपूर्ति श्रृंखला में गैस का उत्पादन, प्रोसेसिंग, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट, तरलीकरण, शिपिंग और रीगैसीफिकेशन शामिल है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जब दुनियाभर में एलएनजी सप्लाई की जाती है, तो हर मेगाजूल ऊर्जा पर औसतन 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के

बराबर उत्सर्जन होता है। वहीं, सामान्य प्राकृतिक गैस से होने वाले यह उत्सर्जन औसतन 12 ग्राम होता है। हालांकि, यह उत्सर्जन अलग-अलग देशों और सप्लाई के रास्तों पर निर्भर करता है। आईईए के मुताबिक 2024 में जितनी भी एलएनजी खपत हुई, उससे जुड़े उत्सर्जन को यदि जोड़ा जाए तो 99 फीसदी से ज्यादा एलएनजी से होने वाला कुल उत्सर्जन कोयले से कम था। औसतन, एलएनजी से कोयले की तुलना में करीब 25% कम उत्सर्जन होता है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी कहती है कि एलएनजी को सिर्फ कोयले से बेहतर बताकर उसकी पर्यावरणीय छवि नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की अभी भी बड़ी संभावनाएं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा तकनीकों की मदद से एलएनजी सप्लाई से होने वाले उत्सर्जन में 60 फीसदी से ज्यादा की कटौती की जा सकती है, और इनमें से कई उपाय तो कम खर्च पर भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ मीथेन के रिसाव को रोककर ही हर साल करीब 9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो एलएनजी से होने वाले कुल उत्सर्जन का करीब 25 फीसदी है। इसमें से आधी कटौती तो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के संभव है। इसके अलावा, एलएनजी प्लांट और गैस सप्लाई करने वाले क्षेत्रों में गैस जलाने (फ्लेयरिंग) को कम करके भी हर साल 50 लाख टन उत्सर्जन घटाया जा सकता है। रिपोर्ट में कुछ और असरदार और किफायती उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे एलएनजी से होने वाला उत्सर्जन काफी हद तक घटाया जा सकता है। इनमें सप्लाई चेन की प्रक्रिया को ज्यादा ऊर्जा-दक्ष बनाना और तरलीकरण संयंत्रों में मौजूद प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण तकनीक का इस्तेमाल करना शामिल है। हालांकि शुरुआत में इसकी लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर गैस उत्पादन इकाइयों और एलएनजी टर्मिनलों को कम उत्सर्जन वाली बिजली से चलाया जाए, तो उत्सर्जन में करीब 11 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की और कमी हो सकती है। ■



सारंडा का बदलाव अब दिखने लगा है: सरयू राय

सारंडा का बदलता परिदृश्य पर रांची प्रेस क्लब में सेमिनार का आयोजन

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और सारंडा बचाओ अभियान के संयोजक सरयू राय ने कहा है कि अब सारंडा बदल रहा है। यह बदलाव दिख भी रहा है। सारंडा के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने अनेक वर्किंग प्लान बनाए। मेटल और माइनिंग की ट्रेडिंग सबके लिए खोल दिये जाने के बाद 2003 के आस-पास इनकी मांग बढ़ गई थी। सारंडा के जितना क्षेत्रफल है, उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए खनन हेतु आवेदन खनन विभाग में आ गया था।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

यहां रांची प्रेस क्लब में आयोजित सारंडा का बदलता परिदृश्य विषय पर आयोजित सेमिनार में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि जिसने कभी माइनिंग का नाम नहीं सुना था, उसने भी माइनिंग लीज के लिए आवेदन कर दिया था। माइनिंग लीज के जो वास्तविक धारक थे, वे सरफेस रेंट के लिए जरूरी धनराशि जमा करा पाने में असमर्थ थे। माइनिंग सेक्टर में बूम आने के बाद वे अन्य उद्योगपतियों के साथ

गठजोड़ करके इसको चलाने लगे। इसके कारण अवैध माइनिंग धड़ल्ले से शुरू हो गई। अवैध माइनिंग के बारे में पूरे भारत में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। उसी दरम्यान सारंडा बचाओ अभियान ने एक पीआईएल फाइल किया। इस पीआईएल को फाइल करने में जस्टिस डॉ. एस. एन. पाठक की अहम भूमिका थी। तब वह सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने कोई फीस नहीं ली और साथ में काम करते रहे। उन दिनों डॉ. पाठक सीनियर वकील थे। बाद में जज बने और अब तो रिटायर भी हो गए लेकिन केस अब तक चल रहा है। इसमें हम लोगों की भी कमी रही। हम लोग उदासीन हो गए। इसी कारण कोई फैसला नहीं हो पाया। अभी दिवाकर उपाध्याय यह केस देख रहे हैं।



गंभीरता को पहचाना और वन संरक्षण कानूनों के उल्लंघन, अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और आदिवासी समुदायों के अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हमारा संविधान कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य और प्रत्येक नागरिक दोनों का कर्तव्य है। इसलिए सारंडा को संरक्षित करना केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह केवल झारखंड के बारे में नहीं है, यह एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधान वन संरक्षक धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि वह जब सारंडा का डीएफओ थे, तब वहां सागवान के बहुत सारे पेड़-पौधे थे। उन्हें वहां इसीलिए भेजा गया कि वह सागवान की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकें। उन्होंने स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया और उनसे ही सागवान की कटाई रुकवाई। सारंडा के परिप्रेक्ष्य में लोगों को रोजगार देकर जोड़ने की जरूरत है।

खनन विभाग के पूर्व उप निदेशक अरुण कुमार ने कहा कि लोगों की यह धारणा बन गई है कि खनन विभाग प्रदूषण फैलाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यह गलत है। खनन विभाग अब बेहद संजीदा हो गया है। यह अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन कर रहा है। देश और राज्य की आधारभूत संरचना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रख्यात पर्यावरणविद प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव ने कहा कि सारंडा 700 पहाड़ों का समूह है जहां अवैध खनन और गलत तरीके से वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है। इसी कारण सारंडा बर्बाद हो रहा है। हाथियों का यह शानदार कॉरीडोर था, जिसे तबाह कर दिया गया है। सारंडा से लगे अनेक इलाकों की यही स्थिति है। सारंडा में सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) का जो खदान है, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, टाटा स्टील के मुकाबले। सेल ने वहां पर माइंस का पहाड़ खड़ा कर दिया है। यह सारंडा की बर्बादी का सबसे अहम कारण है। पूर्व प्रधान वन संरक्षक लाल रत्नाकर सिंह ने कहा कि 1924 में, जब यहां अंग्रेज थे, उन्होंने 850 किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा का नाम दिया। सारंडा बनने के बाद 1968 में सुसंदा वर्किंग प्लान बना था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का गठन हुआ था। यह हाथियों के सबसे बेहतरीन आश्रयस्थली है। देश भर में हाथियों के लिए इससे शानदार शरणस्थली कोई नहीं। इसके संरक्षण की जरूरत है। मनुष्य और वायरस, ये दो चीजें ऐसे हैं जो पृथ्वी के मूल स्वरूप को बर्बाद कर रहे हैं। सारंडा को खनन और परिवहन ने बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधान वन संरक्षक एच.एस. गुप्ता ने कहा कि इंसान खुद को सबसे ज्यादा काबिल समझता है। इसका नतीजा यह है कि आज प्राकृतिक स्वरूप अपने मूल रूप में नहीं है। हमारे पास एक से बढ़ कर एक तकनीकी है। उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए।

खनन विभाग के उप निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि खनन, पर्यावरण और विकास ये सब एक-दूसरे के पूरक हैं। खनन विभाग ने सारंडा समेत राज्य के अनेक हिस्सों में आजीविका के लिए अनेक कार्य किये हैं। डीएमएफटी फंड प्रारंभ किया ताकि स्थानीय जो लोग हैं, उनका जीवन स्तर सुधर सके। अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन युगांतर प्रकृति के अध्यक्ष अंशुल शरण ने किया। स्वागत भाषण प्रो. एमके जमुआर ने किया जबकि विषय प्रवेश डॉ. आर.के. सिंह और धन्यवाद ज्ञापन निरंजन सिंह ने किया। ■

सारंडा बचाओ अभियान, नेचर फाउंडेशन और युगांतर प्रकृति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेमिनार में सरयू राय ने कहा कि सरकार के सभी विभागों के सचिव अपने-अपने विभागों के हित देखते हैं। जहां इंटीग्रल सोच की जरूरत होनी चाहिए, वहां डिफरेंट थॉट काम करता है। कोई इंटीग्रल सोच का ध्यान नहीं रखता। यह चिंता का विषय है। सभी विभागों के हित एक-दूसरे के हितकारी नहीं होते। उन्होंने कहा कि सारंडा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि कंप्लायंस करके 23 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे दें। हमें लगता है कि झारखंड सरकार के अफसर ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र के हित में और अधिक खनन जरूरी होगा तो राज्य सरकार अदालत में अपनी बातों को तार्किक तरीके से रखेगी। उन्हें पक्का यकीन है कि न्यायालय उन्हें खनन के लिए जरूर मौका देगी। श्री राय ने कहा कि माइनिंग करना देश के लिए आवश्यक है, विदेशों के लिए नहीं। विदेशों में बेचे जाने के पहले देश की जरूरतों को भी देखने की जरूरत है। श्री राय ने कहा कि सारंडा की इकोलॉजी सुरक्षित हो, यह जरूरी है। पर्यावरण और खनन विभाग में समन्वय की सबसे अधिक आवश्यकता है।

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) डा. एस. एन. पाठक ने कहा कि सारंडा जंगल जिसे कभी 700 पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता था, जो हरे स्टील के रूप में जाने जाने वाले ऊँचे शाल के पेड़ों और मजबूत आदिवासी समुदायों से भरा हुआ था। सदियों तक सारंडा को एचओ मुंडा और संथाल लोगों के हाथों संरक्षित और पोषित किया गया था। जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं थे। यह संस्कृति परंपरा और पूर्वी भारत की पारिस्थितिकी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी। लेकिन हाल के दशकों में इसे चुपचाप लेकिन लगातार खनन, वनों की कटाई, विस्थापन और कभी-कभी सिर्फ उदासीनता के कारण नुकसान पहुँचाया गया। एक न्यायाधीश के रूप में मुझे अक्सर विकास की जरूरतों को प्रकृति की रक्षा की जरूरत के खिलाफ तौलना पड़ता है और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों दुश्मन नहीं हैं। सच्चे विकास का मतलब प्रकृति को नष्ट करना नहीं है। इसका मतलब है इसके साथ बढ़ना। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्थिति की

‘युगांतर प्रकृति’ पर्यावरण जागरूकता प्रतियोगिता में 24 प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने

- ▶ आप पर्यावरण के साथ अड़ेंगे तो पर्यावरण भी अड़ेगा: दिनेश मिश्र
- ▶ कार्बन फुटप्रिंट्स की सीमा हमने लांघ दी है: प्रजा सिंह
- ▶ पर्यावरण को टेकेन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता: सीपीएन सिंह
- ▶ बी चंद्रशेखरन की अपील: सरयू राय सोलर पैनल सिस्टम को लेकर आवाज बुलंद करें



■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और मासिक पत्रिका युगांतर प्रकृति के संरक्षक सरयू राय ने बुधवार को कहा कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें मुफ्त में प्रदान किये हैं, हम उनका उतना ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने नदियों को गंदा कर दिया। अब कई नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहा। यह स्थिति खतरनाक है।

यहां 4 जून को राजेंद्र विद्यालय के सभागार में पर्यावरण जागरूकता प्रतियोगिता के अध्यक्ष के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए सरयू राय ने कहा कि 1985 के पहले कोई नहीं सोचता था कि कभी बोतलबंद पानी पीने की भी नौबत आएगी। कोई कांसेप्ट ही नहीं था। अब देखिए तो पूरा बाजार बोतलबंद पानी से अटा पड़ा है। इसका कारण यह है कि हमने पानी को गंदा कर दिया और अब शुद्ध पानी पीने के लिए हमें बोतलबंद पानी पीना पड़ रहा है।

सरयू राय ने कहा कि जिस रफ्तार से शहरी विकास हो रहा है, उससे यह डर पैदा हो गया कि शहरों का विकास बेतरतीब न हो जाए। यह बेतरतीब विकास बहुत बड़ा खतरा है। भारत सरकार इस खतरे को समझ रही है और 5 जून को इसी संबंध में देश भर के पर्यावरण से जुड़े सरकारी प्रतिष्ठानों के अदद लोगों की बैठक बुलाई है। संभव है कि उसमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा चर्चा हो।

जमशेदपुर में प्रदूषण के मुद्दे पर श्री राय ने कहा कि जमशेदपुर की हवा हम लोगों ने ही गंदा कर दिया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। हम लोगों को सस्टेनेबल

प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला से पर्यावरण की समस्या बढ़ी: सरयू राय



प्रगति चाहिए। यहां तो सब एकतरफा ही दिख रहा है।

सरयू राय ने कहा कि आने वाले दिनों में पर्यावरण की भयावहता से बचना है तो बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे, जिससे वो पर्यावरण का नुकसान न कर सकें। यह बेहद जरूरी है कि हम पर्यावरण को गंदा न करें।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विख्यात पर्यावरणविद दिनेश मिश्र ने कहा कि अभी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। उन्होंने महाभारत की कहानी सुनाते हुए कहा कि अगर आप पर्यावरण के साथ अड़ोगे तो पर्यावरण भी अड़ेगा। उन्होंने बेंत के किस्से का जिक्र किया। श्री मिश्र ने कहा प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, उनमें समन्वय स्थापित करके ही जिंदगी चल सकती है। बिना समन्वय के तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने पर खासा जोर दिया।

डीएवी स्कूल की प्राचार्या प्रज्ञा सिंह ने कहा कि हमारे दुख का बड़ा कारण अब यह भी है कि कार्बन फुटप्रिंट्स की सीमा हमने लांघ दी है। बर्फ पिघलने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह सब होने लगा है। पहले ऋतुएं के वक्त तय थे। अब सब अनियमित हो गया है। उन्होंने प्रकृति से हर किसी को, खास कर बच्चों को जोड़ने की अपील की।

बिहार एसोसिएशन के सीपीएन सिंह ने कहा कि पर्यावरण को अब



टेकेन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। अब पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी है। पहले अपना घर साफ करना जरूरी है। फिर दूसरे को यह बताना जरूरी है कि अगर तुम्हारा घर साफ नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकता है।



डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के चेयरपर्सन बी चंद्रशेखरन ने पर्यावरण को बड़ा मुद्दा बताते हुए लोगों से अपील की कि वे सरयू राय जी से सीखें। पर्यावरण को लेकर जितने गंभीर श्री राय रहते हैं, उतनी गंभीरता हमें भी लानी होगी। उन्होंने श्री राय से अपील की कि वे सोलर पैनल सिस्टम को लेकर आवाज उठाएं क्योंकि सोलर पैनल सिस्टम बेहद किफायती और पर्यावरण के हितों की रक्षा करने वाला है। इसके पूर्व विषय प्रवेश एसपी सिंह ने कराया। मंच संचालन चंद्रदीप पांडेय जबकि आभार प्रदर्शन अशोक गोयल ने किया। ■

• आयोजन •



विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम

क्विज प्रतियोगिता (सीनियर) में प्रियंका यादव प्रथम, सपन कुमार महतो द्वितीय जबकि कृष्णा कुमार ठाकुर तृतीय रहे। क्विज प्रतियोगिता (जूनियर) में नैवेद्य प्रसाद प्रथम, गौरव कुमार द्वितीय जबकि लक्ष्मी पूर्ति तृतीय स्थान पर रहीं।

भाषण प्रतियोगिता (सीनियर) में पीहू कुमारी प्रथम, कुमारी अनुषिका द्वितीय जबकि अनुष्का कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता (जूनियर) में ऐश्वर्या झा प्रथम, अक्षय कीर्ति कमल द्वितीय और भव्या लक्ष्मी तथा अयांशी राय संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहीं।

चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में अदिति शर्मा प्रथम, नंदिनी साहू द्वितीय तथा तनु कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। उधर, निबंध प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में नितिन कुमार प्रथम, कनिष्क राज द्वितीय और अनुष्का तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में निरुपा कुमारी प्रथम, बेबी कुमारी द्वितीय और श्रेया बिस्वास तृतीय स्थान पर रहीं। हर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र दिया गया। ■



उभयचरों की 41 फीसदी प्रजातियां अब लुप्त होने के कगार पर पहुंचीं

मेंढक, सलामेंडर और केसिलियन जैसे उभयचर जीव दुनिया के कई हिस्सों में अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के अनुसार, उभयचरों की 41 फीसदी प्रजातियां पहले ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।



■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

ड न प्रजातियों पर पहले ही बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक आवास को होते नुकसान और बीमारियों का दबाव है। वहीं जलवायु परिवर्तन के चलते स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बारे में गेटे विश्वविद्यालय, फ्रैंकफर्ट से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में बारिश के पैटर्न में आता बदलाव, सूखा, लू, जैसी बढ़ती चरम मौसमी घटनाएं इनके अस्तित्व को और अधिक संकट में डाल रही हैं। जर्नल कंजर्वेशन बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार मौसम में आ रहे चरम स्तर के बदलाव अब उभयचरों के लिए एक नया गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में मौसम के पिछले 40 वर्षों आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसकी मदद से उन्होंने यह समझने का प्रयास किया है कि कैसे पिछले 40 वर्षों के इन मौसमी बदलावों ने 7,000 से अधिक उभयचर प्रजातियों को प्रभावित किया है।

अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि अस्थाई तालाबों और छोटे जलस्रोतों पर प्रजनन के लिए निर्भर रहने वाली प्रजातियां, जैसे मेंढक, सूखे और असमय गर्मी के कारण अपने अंडे और लार्वा के विकास में असफल हो रही हैं। इससे इनकी आबादी घट रही है। अध्ययन के निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हैं जिन क्षेत्रों में लू और सूखे की घटनाएं बढ़ीं हैं। वहां 2004 के बाद से रेड लिस्ट में शामिल उभयचर प्रजातियों की स्थिति और खराब हुई है। विश्लेषण में यह सामने आया है कि चरम मौसमीय घटनाओं के बढ़ने और उभयचरों की घटती संख्या के बीच सीधा संबंध है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर इवान ट्वोमी ने प्रेस विज्ञापित में जानकारी

दी है कि, “उभयचर जीव प्रजनन के लिए अस्थाई जलस्रोतों पर निर्भर होते हैं, इसलिए सूखा और तापमान में बदलाव उनके लिए खासतौर पर खतरनाक हैं, क्योंकि इससे उनके प्रजनन क्षेत्र समय से पहले सूख जाते हैं।”

इतना ही नहीं ज्यादा गर्मी में मेंढकों की त्वचा और सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है, जबकि अत्यधिक ठंड कई प्रजातियों को बीमारियों जैसे कि ‘चिट्रिड फंगस’ के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि यूरोप, अमेजन और मेडागास्कर में यह जीव विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में, जहां मेंढकों की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं, वे बढ़ती गर्मी और लू का सामना कर रही हैं। वहीं यूरोप में पड़ता सूखा उभयचरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर सलामेंडर इस बदलती जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि यह जीव नमी पर निर्भर रहता है। मध्य यूरोप में स्थिति खासतौर पर चिंताजनक है। जलवायु पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले वर्षों में यहां सूखे की अवधि और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं। अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता प्रोफेसर लीसा शुल्ते ने चेताया, “मध्य यूरोप में पाए जाने वाले आधे से अधिक सलामेंडर पहले ही बढ़ते सूखे का सामना कर रहे हैं। वहीं आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं।” इसी तरह मेडागास्कर में भी अनेक उभयचर प्रजातियां गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि इन जीवों को बचाने के लिए हमें तत्काल लक्षित संरक्षण उपायों की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, कई उपाय इन संकटग्रस्त प्रजातियों की मदद कर सकते हैं, जैसे छोटे संरक्षित क्षेत्र बनाना जहां ये जीव सुरक्षित रह सकें। प्राकृतिक दलदली क्षेत्रों में सुधार करना ताकि इन्हें रहने और प्रजनन के लिए बेहतर माहौल मिल सके। ■

देवनद-दामोदर महोत्सव 2025



बोकारो में राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरयू राय की तारीफ की

नदियों की स्वच्छता के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी: राज्यपाल

» झारखंड में 45 स्थानों पर आयोजित हुआ देवनद-दामोदर महोत्सव : अंशुल शरण

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि इन दिनों देश भर में नदियां उथली हो रही हैं और उनकी सफाई नहीं होती। इसी कारण से देश की नदियां समस्याग्रस्त हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि वह जब अटल जी की सरकार में कुछ दिनों के लिए जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने पाया कि देश में नदियों को लेकर जितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। उन्हें यह देख-जान कर अच्छा लगा कि सरयू राय ने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। उन्हें बधाई।

बोकारो के तेलमचो पुल के नीचे 5 जून को युगांतर भारती के तत्वावधान में आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव-गंगा दशहरा के मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश भर की नदियों की स्थिति खराब हुई है। अब यह जरूरत



महसूस की जा रही है कि नदियों के लिए हम सभी लोग मिल कर काम करें। सिर्फ दामोदर के लिए ही नहीं, सभी नदियों के लिए।

राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विशेष है। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा, दोनों एक साथ आयोजित हो रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में आज लोग धरती, जंगल, नदियाँ और प्रकृति को बचाने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम सनातन परंपरा में गंगा अवतरण को स्मरण कर रहे हैं। गंगा दशहरा हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही नदियों को मां कहा, उनके जल को मोक्षदायिनी माना। यहां गंगा तो नहीं, लेकिन दामोदर है। और जैसे गंगा उत्तर भारत की आत्मा है, वैसे ही दामोदर झारखंड की जीवनरेखा है और दामोदर भगवान विष्णु के सहस्र नामों में से भी एक है।

राज्यपाल ने कहा कि युगांतर भारती ने पर्यावरण को जन आंदोलन बना दिया। इसके लिए युगांतर भारती को बधाई। वास्तव में इस संस्था ने बढ़िया काम किया है। दामोदर सिर्फ एक नद नहीं बल्कि झारखंड की जीवनरेखा है। इसी के किनारे बोकारो स्टील प्लांट और अन्य उद्योग लगे हैं। औद्योगिक विकास खूब हो रहा है लेकिन इस दौड़ में दामोदर नदी को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरयू राय जैसे जागरूक जनप्रतिनिधि और युगांतर भारती जैसे संगठन ने बढ़िया काम कर अपनी प्रभावी स्थिति दर्ज की है। सरयू राय ने दामोदर को बचाने के लिए लंबा आंदोलन छेड़ा। पदयात्राएं कीं। लोगों को जगाया। उन्हें समझाया। अब परिणाम साफ दिख रहा है। दामोदर का पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले से अब की स्थिति बदली है। नदियों की स्वच्छता संस्थाओं या सरकारों तक की ही जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक वक्त गंगा भी बहुत खराब स्थिति में थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गंगा की स्वच्छता हेतु व्यापक कार्य किया गया। अब तो लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने कहा कि दामोदर भगवान विष्णु जी के सहस्र नामों में से एक है। जहां से दामोदर का उद्गम है, उसे हमारे अध्ययन दल के लोगों ने खोजा। खोजी स्थान से 25 किलोमीटर तक इस नद का नाम देवनद है। खलारी के बाद से इसका नाम दामोदर पड़ा।

सरयू राय ने कहा कि दामोदर के 200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग-धंधे हैं। दामोदर के जल के कारण ही यहां उद्योगों का प्रादुर्भाव हो सका। अब यही उद्योग-धंधे भस्मासुर की तरह दामोदर को नष्ट करने पर उतारू हो गये थे। हम लोगों ने मूवमेंट चलाया। आप सभी का सहयोग मिला। अब स्थिति में काफी परिवर्तन आया है।

श्री राय ने कहा कि दामोदर के उद्गम स्थल से पंचेत जलाशय तक 45 स्थानों पर देवनद-दामोदर महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम यहां हो रहा है। इस तरह के महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य जनजागरूकता है। लोग प्रकृति को समझें। दामोदर समेत अन्य नदियों के बारे में लोग जानें और इन्हें साफ-

‘युगांतर भारती ने पर्यावरण को जन आंदोलन बना दिया। इसके लिए युगांतर भारती को बधाई। वास्तव में इस संस्था ने बढ़िया काम किया है।’

-संतोष गंगवार
राज्यपाल, झारखंड



सुथरा रखने का प्रयास करें।

श्री राय ने कहा कि जिन-जिन जगहों पर हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करते हैं, वहां एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह विकास कार्य हो, अच्छा घाट बन जाए तो लोग वहां घूमने आ सकेंगे। हम लोग यहां तेलमच्चो के नीचे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस स्थान को भी विकसित किया जा सकता है। यह एक सुरम्य स्थान बन जाएगा तो लोग यहां आया करेंगे।

बोकारो की विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि दामोदर महोत्सव के लिए सरयू राय ने गरगा और दामोदर नदी के संगम स्थल तेलमच्चो को चुना और झारखंड के राज्यपाल को गंगा आरती के लिए लेकर आए, इसके लिए बोकारो की समस्त जनता की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोकारो के लोगों से और ज्यादा संवेदनशील होकर दामोदर और इसकी सहायक नदियों का संरक्षण करने तथा साफ-सुथरा रखने का आह्वान किया।

आईआईटी (आईएसएम) के प्रोफेसर अंशुमाली ने कहा कि दामोदर झारखंड के अस्सी हजार वर्ग किलोमीटर सिंचित क्षेत्र में से पच्चीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करती है। दामोदर की सहायक नदियां जैसे जमुनिया, कटरी और गरगा को बचाने, उन्हें संरक्षित करने की आज सबसे अधिक जरूरत है। इन नदियों को उनकी खोई जमीन वापस लौटाना होगा। हमें उनका पुराना अस्तित्व, पुराना स्वरूप लौटाना होगा। तभी गंगा और दामोदर जैसी बड़ी नदियों का अस्तित्व बचेगा। आज सर्वे मैप पर छोटी नदियों का उल्लेख तो जरूर है मगर धरातल पर देखे तो इनका अस्तित्व नष्ट हो चुका है। इसके पूर्व स्वागत भाषण युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण ने किया। उन्होंने बताया कि झारखंड के 45 स्थानों पर आज देवनद-दामोदर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह महोत्सव बीते 2006 से लगातार चला आ रहा है। यह संयोग है कि आज ही पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा भी है।



बच्चों को शिद्धत से कला सिखा रहे हैं डॉ. विनोद रंजन

जहां रचनात्मकता है, वहां कला है। कला का संसार ऐसा है, जिससे मुझे अलग कर दें तो शायद मैं जी ना पाऊं। अभी डीपीएस, रांची में सीनियर आर्ट टीचर (पीजीटी) हूं। जिम्मेदारियां बहुत सी हैं। कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं। हां, बच्चों को पूरी शिद्धत से कला के हर पहलू के बारे में बता रहा हूं। अपने काम में ईमानदारी रहती है।



■ आनंद सिंह

आपने ठीक कहा कि बहुत सारे बच्चे कला के क्षेत्र में नामांकन तो करा लेते हैं पर परफार्म नहीं करते। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ कला क्षेत्र ही नहीं है। किसी भी विषय को आप उठा लें, आपके इस तरह के केस मिल

जाएंगे। मैं किसी को ब्लैक एंड व्हाइट का कंपोजीशन दे दूं तो वह खुद से प्रयास नहीं करेगा। इंटरनेट से उठाएगा और थोड़ा बाएं-दाएं करके उसे अगली सुबह पेश कर देगा। एक शिक्षक के रूप में मैं जानता हूं कि बच्चा भविष्य से खेल रहा है। मैं समझाता हूं। माता-पिता से भी कहता हूं। इसके बाद भी कोई सुधार न हो तो क्या कहा जा सकता है।

कलाजगत में आप कल्पनाशीलता के धनी नहीं हैं, चिंतन नहीं है, कुछ नया

• कला जगत •



कर गुजरने की क्षमता नहीं है, कुछ क्रिएट करने का माद्व नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं, कुछ और हो सकते हैं।

कक्षा पांच में ही मैंने यह तय कर लिया था कि मुझे आर्ट के क्षेत्र में जाना है। मेरा कांसेप्ट डे वन से क्लियर था। कोई भटकाव नहीं। 1992-93 से मैं इस पेशे में हूँ। मोटे तौर पर 34-35 साल का अनुभव हो गया है। मैं किसी किस्म के कन्स्यूजन में जीने में यकीन नहीं रखता। डीपीएस में पढ़ा रहा हूँ। पीजीटी हूँ। डॉक्टरेट कर रहा है। मैं पढ़ता हूँ। अपने अनुभवों से बच्चों को पढ़ाता हूँ। पिछले कई साल से आर्ट में मेरे विद्यालय का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा है। हमारे स्कूल का रिजल्ट सदैव यूनिक होता है।

मैंने अब तक 60 से ज्यादा आर्ट कैप किये हैं। कुछ मैंने लगाया, कुछ में पार्टिसिपेट किया। मैं आर्ट एग्जिबिशन में भी जाता हूँ। 61 से ज्यादा आर्ट एग्जिबिशन अटैन्ड कर चुका हूँ। 25 से ज्यादा प्रकाशन हैं मेरे। विविध विषयों पर लिखता रहा हूँ। मेरे लेख पत्रिका, जर्नल्स और अखबारों में छपते रहे हैं। मुझे देश भर के संस्थानों द्वारा नौ पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

मेरे पिताजी बीआईटी मेसरा में थे। वह वहां 10-12 साल रहे। मेरा जन्म 1970 में यहीं पर हुआ। घर में पढ़ने-लिखने का माहौल था। इस पढ़ने-लिखने के माहौल के कारण ही कक्षा पांच में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है। मैं जेबीएम का प्रोडक्ट रहा। कॉलेज के रूप में शांतिनिकेतन गया। वहां से बैचलर और मास्टर डिग्री, दोनों फाइन आर्ट्स में की। बाद में डॉक्टरेट भी किया। शांतिनिकेतन के दिन भी शानदार रहे। एक अनुशासन में बंध कर मैंने वहां काफी कुछ सीखा और जो सीखा, उसके आधार पर सृजन किया।

पहले ही मैंने तय कर लिया था कि मैं आर्ट लाइन में जाऊंगा तो जरूर और सृजन भी करूंगा लेकिन उसका फोकस प्वाइंट टीचिंग से होकर गुजरेगा। मुझे कई विद्यालयों से अच्छी नौकरियां ऑफर हुईं। कुछ स्थानों पर मैंने पढ़ाया भी। अंत में डीपीएस, रांची में आया और यहीं का होकर रह गया। डीपीएस रांची के लिए जो वांट निकला था, उसके आवेदन में मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि यह आवेदन सिर्फ रांची के लिए है। एक अनोखे अंदाज में रांची के लिए मेरा चयन हुआ, जबकि वेकेंसी बोकारो के लिए निकली थी। मुझे रांची इसलिए आना पड़ा, क्योंकि माताजी बीमार थीं। उन्हें मेरी जरूरत थी। इसलिए मैंने हर ऑफर को ठुकरा कर रांची के ऑफर को ही पकड़ा।

(जैसा प्रधान संपादक आनंद सिंह से बातचीत में बताया)





प्रथम पुरस्कार-501 रुपये नकद

द्वितीय पुरस्कार-351 रुपये नकद

तृतीय पुरस्कार-251 रुपये नकद

नियम और शर्तें

1. आपको युगांतर प्रकृति का यह अंक बेहद गौर से पढ़ना है।
2. इसी अंक में प्रकाशित विभिन्न लेखों से हम 20 सवाल करेंगे। उन 20 सवालों के जो सही-सही जवाब देंगे, उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
3. अगर 20 में से 20 सवालों के सही जवाब कई लोग देते हैं तो पुरस्कार उन्हें मिलेगा, जिनका जवाब सबसे पहले आएगा। यानी, जो पहले जवाब देंगे, वो पुरस्कार के हकदार होंगे।
4. जवाब सिर्फ ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। ई-मेल आईडी है yugantarprakriti@gmail.com
5. कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, एक रंगीन फोटो, बैंक खाता अथवा यूपीआई आईडी अथवा क्यूआर कोड अवश्य भेजें।
6. विजेताओं को धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी और अगले अंक में उनकी तस्वीर के साथ उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
7. इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। उम्र, लिंग का कोई बंधन नहीं है।
8. इस प्रतियोगिता में युगांतर प्रकृति परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते।
9. निर्णायक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। उसे किसी भी सूरत में, कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

गौर से पढ़िए युगांतर प्रकृति

हमारे **20 सवालों** के जवाब दीजिए
और, पाइए आकर्षक पुरस्कार
पढ़ो और पुरस्कार पाओ (5)

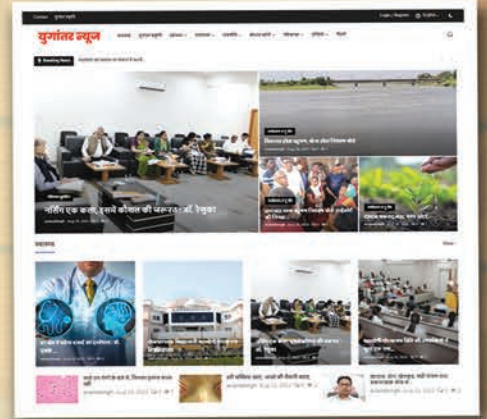
1. टाटानगर के किस विद्यालय में युगांतर प्रकृति के बैनर तले चित्रकला प्रतियोगिता हुई?
2. सारंडा पर सेमिनार किस शहर में हुआ?
3. झारखंड के राज्यपाल का क्या नाम है?
4. युगांतर भारती के अध्यक्ष का क्या नाम है?
5. उभयचरों की कितनी प्रतिशत आबादी लुप्त होने के कगार पर पहुंची है?
6. डीएवी स्कूल, जमशेदपुर की प्रिंसिपल का क्या नाम है?
7. जमशेदपुर से गहरे जुड़े बी. चंद्रशेखरन कौन हैं?
8. जमशेदपुर के एक विद्यालय से जुड़े सीपीएन सिंह कौन हैं?
9. इस वर्ष दामोदर महोत्सव का मुख्य आयोजन कहां हुआ?
10. 2025 के दामोदर महोत्सव आयोजन के मुख्य अतिथि का क्या नाम था?
11. दामोदर महोत्सव आयोजन किन संस्थाओं ने किया?
12. अभी भारत में कितने बाघ हैं?
13. क्या भारत में बाघों की गिनती का काम शुरू हो गया है?
14. वन्य क्षेत्र से जुड़े पीटीआर का फुल फार्म क्या है?
15. दलमा प्राणी अभ्यारण्य कहां है?
16. सारंडा में कुल कितनी पहाड़ियां हुआ करती थीं?
17. सारंडा किस जिले में अवस्थित है?
18. सारंडा के लिए आंदोलन करने वाले वर्तमान विधायक का क्या नाम है?
19. तेल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला शब्द एनएलजी का फुल फार्म क्या है?
20. प्लास्टिक से मुक्ति के लिए आप क्या करेंगे?

युगांतर न्यूज

एक ऐसा न्यूज पोर्टल जिसमें आपको मिलेंगी

राजनीति, हेल्थ और
पर्यावरण की खबरें

www.yugantarnews.in पर पढ़ें



हमारा  YouTube Channel देखें [yugantarnews](https://www.youtube.com/yugantarnews)

With Best Compliments From
दामोदर बचाओ आंदोलन





युगांतर भारती

ने पर्यावरण को जन आंदोलन बना दिया।

इसके लिए युगांतर भारती को बधाई।

वास्तव में इस संस्था ने बढ़िया काम किया है।

-श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्यपाल, झारखंड



5 जून 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय ने बोकारो के तेलमचो में युगांतर भारती के बारे में जो बोला, उसके पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। वह संघर्ष हमारा साथी है। उसी संघर्ष की राह पर हमें आगे भी चलना है और हम संघर्ष करेंगे।

जीरो एरर, 100% सटिस्फैक्शन हमारी पहचान है।



युगांतर भारती
भरोसा जीतने का माद्दा